श्री सिकन्दर बख्त : मैं अर्ज करूं कि दिल्ली की तमाम जमीन अण्डर सैक्शन–4 में नोटिफाइड हैं और बहुत डिकेड पहले जब भी आप जमीन एक्वायर करते हैं, तो किसान को जिसकी वह जमीन है, उसको कम्पनसेट करते हैं, तो जो अण्डर सेक्शन–4 में नोटिफाइड है, उसके हिसाब से करते हैं।

How is the Government affected by the increase in the cost of land today?

شری سکندر بخت : میں عرض کروں کہ دلی کی تمام زمین انڈر سیکشن ۴ - میں نوٹیفائیڈ ہیں اور بہت ڈکیڈ پہلے جب بھی آپ زمین اکوائر کرتے ہیں تو کسان کو جس کی وہ زمین ہے اس کو کمپنسیٹ کرتے ہیں تو جو انڈر سیکشن ۴ میں نوٹیفائیڈ ہے اس کے حساب سے کرتے ہیں۔

श्रीमती शीला कौल : कम्पनसेशन जो है, उसका रेट बढ़ गया है। जैसा मैंने पहले आप से कहा आप दाम पहले जो 1.95 लाख पर एकड़ था तीन-चार साल पहले, वह अब बढ़ कर 6 लाख पर एकड़ हो गया है। लैण्ड के रेट बढ़ गये हैं, लैण्ड की कीमतें बढ़ी हैं, इसी हिसाब से सरकार दे रही है।

श्री एस. एस. सुरजेवाला : आपने ही करवाया था। जब आप 78 में मंत्री थीं, उस वक्त जो दाम थे, उसमें अब चेंज आ गया है। (**व्यवधान**)

MR. CHAIRMAN: You please sit down.

SHRI SOMAPPA R. BOMMAI: He was in charge of the same Ministry. (*Interruptions*) . . .

SHRI S. JAIPAL REDDY: That is the reason why he should not have put the question. (*Interruptions*) . . .

MR. CHAIRMAN: Question No. 562, Shri Gopalsinh G. Solanki.

Expert Group on School Curriculum

*562. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state

(a) whether any research for the improvement of school curriculum has been undertaken;

(b) whether any expert group has been constituted for the purpose;

(c) if so, the outcome thereof;

(d) whether any recommendations have been made by the group in this regard; and

(e) if so, the details of the recommendations made by the group and the action taken thereon ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) to (e). A Statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

Deveolpment and improvement of school curriculum is an ongoing process. One of the main objectives of the National Council of Educational Research and Training (NCERT) at the national level and of the State Councils of Educational Research and Training (SCERTS) at the state level is to develop and continuously improve school curriculum. At secondary level the Boards of School Education also attend to this work. As such it is not for any one expert group to do such work and no such group has been appointed.

Some of the notable initiatives in improvement of school curriculum in recent years have been :

(i) Development of National Curricular Framework in 1988 by NCERT to reflect the concerns of National Policy on Education 1986.

(ii) Developing and defining Minimum Levels of Competence for Primary level to ensure a certain minimum level in learning at that level.

(iii) Report of the Yash Pal Committee in 1993 to assess whether the curriculum load on students is excessive.

(iv) International Conference-cum-Seminar by Council of Boards of School Education in India to discuss what curricular improvements or adjustments would be called for to prepare students for the society and environment of 21st Century.

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI : Sir, so far as the answer is concerned, I do agree with the Minister that the development and improvement of school curriculum is a constant process. I would like to draw the attention of the Government to the report the Estimates Committee wherein it has made some suggestions to the NCERT and SCERTS. I would like to know whether the Government has taken note of these recommendations. So far as the improvement of curriculum is concerned, I would like to know the action which has been taken so far.

KUMARI SELJA : Sir, as the Member himself has pointed out, this is a continuous process and the NCERT is constantly pursuing this with the SCERTS.

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI ; Today we find that the children right from the KG to the school level have got a lot of burden. The parents and the children are very much busy with the studies. Therefore, they cannot take any part in extra-curricular activities which, she said, has increased. At the same time, we find and it is an admitted position that the Government set papers out of the uncovered portions. In the case of mathematics we found it recently. I would like to know whether the Government is going to change the method of examination, whether a new method of studies is going to be introduced where no examination would be required for mathematics and other things, and, at the same time, during the examination the students would be graded according to their calibre.

KUMARI SELJA : Sir, the same question was raised last time also. As I replied earlier, there is no such proposal under consideration at the moment to change the examination system because we find it quite adequate.

श्री राधाकिशन मालवीय : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पिछले सेशन में एच०आर०डी० के जो मिनिस्टर हैं, आदरणीय श्री अर्जुन सिंह जी, उन्होंने यह कहा था कि हम प्राइमरी स्कूल के बच्चों पर जो पाठ्य-पुस्तकों का बोझ है, उसको कम करेंगे। इसके लिये सेन्ट्रल लेवल पर राष्ट्रीय शैक्षिणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् बनी हुई है और राज्य स्तर पर राज्य शैक्षणिक अनुसाधन परिषद् बनी हुई है, जो पाठ्य-पुस्तकों को निर्धारित करने का काम करती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं' उनकी पाठ्य-पुस्तकें और जो उनका निर्धारित सिलेबस है, क्या उसमें व्यावसायिक, बौद्धिक इतिहास, साइन्स एण्ड टेक्नालाजी और मैथेमेटिक्स विषयों पर संक्षिप्त पाठ्य-पुस्तकें निर्धारित करने की कोई योजना है?

कुमारी शैलजा : अभी हाल ही में 1990 में सारे कोर्स रिवाइज्ड किये गये थे, जिसमें इन सब बातों को ध्यान में रखा गया है। इसको व्यापक रूप से दुबारा देखा गया और दुबारा इस पाठ्य-क्रम फ्रेम किया गया था। नयी पुस्तकें एन०सी०ई०आर०टी० ने 1990 में रिवाइज्ड की थीं।

श्री राधा किशन मालवीय : पिछले सेशन में मंत्री जी ने कहा था कि आने वाला जो सेशन होगा, जुलाई, 1994 से, उसमें प्राइमरी बच्चों का जो सिलेबस है, उसको कम करेंगे। मैंने यह पूछा है। अब जुलाई 94 से पढ़ाई का सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो क्या इस सेशन

में बोझ कम करने के लिये जितने विषय हैं, उनका बोझ आधा करेंगे ?

कुमारी शैलजा : यह उससे हटकर दूसरा क्वेश्चन है। जो आप बोझ कम करने की बात कर रहे हैं।

We had set up the Yashpal Committee to reduce the load, the so-called physical load on the young children and young students.

यशपाल कमेटी ने जो रिपोर्ट दी, उसमें यह बात सामने आई कि जो बोझ है वह सबसे ज्यादा मेंटल है।

Especially, the load of ignorance that accumulates over the years because what a child learns in the first section is limited and what he does not learn is more. So, it gets accumulated. Hence, our concern is to reduce that load of ignorance which a child accumulates. I would like to point out that this so-called physical load is more prevalent in cities and urban areas rather than in rural areas. Keeping this in view, the Yashpal Committee report was discussed by the Central Advisory Board. As advised by Prof. Yashpal himself, it requires widespread discussions and seminars. Sir, it has been referred to the respective States. They should go in for this kind of seminars and discussions. Ultimately, it is up to the States to follow this system and reduce the load on the young children because 99 per cent of the schools are with the States.

श्री चतुरानन मिश्र : सभापति महोदय, एक कहावत है कि अगर नहीं कोई तरक्की करनी हो, तो कमेटी सेट-अप कर दो। नहीं कुछ काम करना हो, तो कमेटी सेट-अप कर दीजिये। वह तो अलग सवाल है। करीकुलम को इम्प्रूव करने का एक मात्र उद्देश्य है, शिक्षा के स्टैण्डर्ड में उन्नति हो।......(व्यवधान).. जरा मंत्री जी, कृपा करेंगे, क्या आप ? डिस्ट्रबेंस हो रहा है।

हमारा उद्देश्य है कि शिक्षा का स्तर ऊंचा किया जाए। पिछले 10-15 वर्षों से। ऐसी चर्चा लगातार चल रही है कि शिक्षा का स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि—वर्तमान सरकार को आए हुए करीब 1000 डेज से अधिक हो गया। तो इस पीरियड में इस देश की बात छोड़ दीजिये क्या सैन्ट्रल स्कूलों के स्टैंडर्ड में तरक्की हुई है या प्राइमरी में, सेकेंडरी में या कालेज में या यूनिवर्सिटी में कहीं भी क्या कोई तरक्की हुई है? अगर कुछ भी तरक्की हुई तो मंत्री महोदया हाउस को सूचित करेंगी?

कुमारी शैलजा : सर, हम यहां पर स्कूल एजूकेशन की बात कर रहे हैं और जैसा कि मैंने बताया कि तकरीबन आज हमारे देश में 8 लाख के करीब स्कूल्स है।

तकरीबन स्टेट्स के पास हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में 1200 स्कूल हैं जिनमें केंद्रीय विद्यालय आ जाते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय आ जाते हैं और सी०बी०एस०ई० आ जाता है। उसको ध्यान में रखते हुए ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें एक्शन लें

We are sending communications to these agencies for the implementation of this report... (*Interruptions*)

SHRI CHATURANAN MISHRA : This is not what I have asked.

KUMARI SELJA: May I just finish? (*Interruptions*)

SHRI CHATURANAN MISHRA: I asked whether any improvement had taken place anywhere, either in the Central sector or in the State sector, either in the private schools or in the public schools.

KUMARI SELJA : This is a general question...

MR. CHAIRMAN : You say, "All-round improvement has taken place."

SHRI SONTOSH MOHAN DEV : Hon. Member is satisfied.

श्री राज नाथ सिंह : समापति महोदय माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि नेशनल काउंसिल आफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग और स्टेट काउंसिल आफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग का मैन आब्जेक्टिव स्कूल करिकुलम में समय-समय पर इम्प्रूवमेंट करना है । लेकिन मेरी निश्चित जानकारी है कि इस देश के कई राज्यों में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में स्टेट काउंसिल आफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिग की रिकमेंडेशन पर 1992 में वहां जो हिस्टरी मैथमेटिक्स और हिन्दी के पाठ्यक्रमों में कुछ संशोधन और परिवर्तन किए गए थे लेकिन वर्तमान सरकार ने बिना स्टेट काउंसिल आफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की संस्तुति प्राप्त किए सामान्य शासनादेश के द्वारा उन सारे संशोधनों और परिवर्तनों को रद्द कर दिया है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस मामले में वे हस्तक्षेप करने की कृपा करेंगे और साथ ही यह भी जानना चाहूंगा कि क्या स्टेट काउंसिल आफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिग को कुछ विशेष स्वायत्तता इस प्रकार की प्रदान करने की कोशिश भारत सरकार करेगी ताकि राज्य सरकारें मनमाने तरीके से हस्तक्षेप करना बन्द कर दें ।

सभापति महोदया, दूसरा प्रश्न इसी के साथ में समान पाठ्यक्रमों के बारे में पूछना चाहूंगा क्योंकि हर स्टेट में जहां पर कुछ गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट कालेज चलते हैं वहां पर बहुत सारे प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट कालेज भी चलते हैं लेकिन उनके करिकुलम में बहुत बड़ा अन्तर होता है भिन्नता होती है । हर स्टेट में करिकुलम के मामले में एक समानता हो इस दृष्टि से क्या भारत सरकार विचार करेगी

कुमारी सैलजा : सभापति जी जहां तक लास्ट प्वांइट का सवाल है आदरणीय सदस्य ने खुद ही कहा है कि हर स्टेट में इसके बारे में स्टेट ही निर्णय ले पाएगी । उनके जो स्कूल और कालेज हैं, उनके बारे में सेंटर उन्हें कुछ नहीं कह सकता कि जो डिफरेंट स्कूल और कालेज हैं गवर्नमेंट के और प्राईवेट कि वह किस तरह से इनको करें । It is the States' concern. As regards curriculum, Sir, he referred to some changes that have taken place in the history books. W received a lot of complaints on that and we have taken a decision. As per our policy, there are four components which should form part of the curriculum all over the country and these are a study of the India's freedom movement, Constitutional obligations and a number of other points, on which the curriculum, the syllabus of different States should be based. The different SCERTS are supposed to keep this in mind. Sir, in a Conference of the State Education Ministers and eminent educationists, which was convened on 1-2-93 for evolving a consensus opinion on the measures to be taken to prevent such kinds of distortions and changes, there was a consensus that a Plan of Action with the required Constitutional and legal authority should be formulated and the modalities for enforcing it should be provided. So, we are trying to work on that, Sir.

SPDA Centres in U.P.

*563. **DR. MURLI MANOHAR JOSHI:**
SHRI TIRLOKI NATH CHATURVEDI:†

Will the Minister of HUMAN RESAURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether U.P. Government have submitted schemes for setting up SPDA Centres in Sefai (Etawah), Bijnor, Saharanpur, Sultanpur, Hamirpur and Ghaziabad, if so, when was each scheme submitted and what is the present status of each scheme; and

(b) by when the Central Government's approval will be given for each scheme?

†The Question was actually asked on the floor of the House by Shri Triloki Nath Chaturvedi.